खाकी

राजनीति का नक्सल प्रश्न और पुलिस समाधान

विकास नारायण राय

बंगाल चुनाव प्रचार से बमुश्किल समय निकालकर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 पुलिस जवानों की शहादत के सन्दर्भ में 'बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा' जैसी रस्मी बातों के बाद छत्तीसगढ़ जाकर बदला लेने की हुंकार भी भरी। पुलिस समाधान पर डटी सरकार के प्रतिनिधि की भाषा यही होनी थी। जवाब में नक्सलियों ने जो पत्र सार्वजनिक रूप से जारी किया है, उसके स्वर राजनीतिक हैं। ये कोई नये दांव-पेंच नहीं हैं। एक ओर सरकार पूर्ण हथियार समर्पण से शुरुआत चाहती रही है, जबकि नक्सली लगातार सिग्नल देते आये हैं कि वे एक राजनीतिक समझौते का इंतजार करना चाहेंगे।

बीजापुर में एक व्यापक पुलिस-सीआरपीएफ ऑपरेशन की खूनी असफलता ने, स्वाभाविक था, एलडब्लूई (लेफ्ट विंग एक्सट्रीमइज्म) के विरुद्ध पुलिस एक्शन के तमाम रणनीतिक आयामों पर बहस छेड़ दी है। एक नियोजित हमले में अपने शवों के बिना जमीन छोड़ना निश्चित ही पेशेवर विमर्श को दावत देना होता है। यहाँ तक कि टक्कर में सेना-वायु सेना को उतारने तक की वकालत करने वाले भी पहले की तरह मुखर हो उठे हैं, मानो भारत सरकार के सामने यह भी एक

अमित शाह की रस्मी बातें

विकल्प हो। जैसे कि, न जेनोसाइड के अंतरराष्ट्रीय आरोपों से भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी और न उत्तर-पूर्व और कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा में लम्बे समय तक सेना के इस्तेमाल की निरर्थकता के उदाहरण सामने हैं।

चिदंबरम, तत्कालीन यूपीए सरकार के शक्तिशाली गृह मंत्री, ने नवम्बर 2009 में ऑपरेशन 'ग्रीन हंट' में सीआरपीएफ को झोंकने के समय एलडब्लूई के घुटने टिकाने के लिए 3 वर्ष का लक्ष्य रखा था। हालाँकि, जानकारों ने इसे तब भी हास्यास्पद माना था कि ऐसा अतिरेकी दावा सरकार में विरोधी स्वरों को शांत रखने और इस नीतिगत फैसले को पीछे से संचालित कर रहे कॉरपोरेट हितों को संतुष्ट करने के लिए किया गया होगा। 2006 में तत्कालीन मितभाषी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो अपेक्षाकृत संयत आकलन के लिए जाने जाते हैं, एलडब्लूई को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा चिह्नित कर चुके थे। लेकिन कारपोरेट भावनाओं को ठोस कार्यवाही चाहिए थी और यह एक लम्बे समय तक चलने वाले पुलिस एक्शन के रूप में होने जा रही थी, जिसकी तब से कीमत सैकड़ों अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन, नियमित छोटे बड़े पुलिस बलिदान और गंभीरतम मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में देश चुकाता आया है।

हालाँकि, एलडब्लूई थिएटर में, राजनीति और पुलिस रणनीति का वाटरशेड सन 2004 को मानना चाहिए। इस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली, कठोर पुलिस एक्शन की समर्थक, पहली एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हुई और राहुल गाँधी के सत्ता में दखल वाली मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार केंद्र में काबिज हुई। इसी वर्ष परस्पर लड़ते और पुलिस एक्शन में कमजोर पड़ते विभिन्न राज्यों में एलडब्लूई के 40 बंटे समूहों ने, जिनमें शीर्ष दो थे पीडब्लूजी और एमसीसीआई, एक बैनर – सीपीआई (माओवादी)– तले आने और दण्डकारण्य को अपना मुख्य क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया। उनकी इस राजनीतिक रणनीति ने आंध्र के 'ग्रे हाउंड' जैसे आक्रामक पुलिस अभियानों को बाजू में छोड़ दिया। साथ ही एलडब्लूई की कैडर और फण्ड की समस्या भी निपट गयी। यह एक खुली जानकारी है कि जो कारपोरेट दण्डकारण्य की अपार प्राकृतिक सम्पदा की लूट में लगे हैं, उन्हीं की लेवी और सरकारी लूट के चंदे से माओवादी अपना 1500-2000 करोड़ का सालाना बजट जुटा लेते हैं। पुलिस एक्शन का आत्मघाती पक्ष आज छिपा न भी रह गया हो, लेकिन इस नीति को सरकारी स्वीकार्यता मिलने से पहले निश्चित तौर पर एक अंदरूनी कशमकश से गुजरना पड़ा था। अप्रैल 2008 में यूपीए सरकार के प्लानिंग कमीशन ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड और ओड़िसा के अपने अध्ययन 'डेवलपमेंट चैलेंजेस इन एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया' में पाया कि सम्बंधित क्षेत्रों के आम लोगों का वहां की पुलिसिंग में विश्वास नहीं था, जबकि नक्सल समाज के कमजोर तबकों के साथ खड़े होंगे, ऐसा भरोसा था। 'नक्सल अभियान' के फलस्वरूप गरीब के ऊपर शासकीय नीति के अंतर्गत पुलिस ज्यादतियां होती हैं। नक्सल समर्थित हलचल को बिना उसके न्याय तत्व को देखे बर्बरता से कुचल दिया जाता है। प्रशासन के लिए नक्सल मजबूती और वृद्धि को कुचलना कहीं आवश्यक हो जाता है, बजाये सही आकांक्षाओं का जवाब देने के। जो भी शक्तिशाली के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे नक्सल बताकर जेल भेज देते हैं या खामोश कर देते हैं। नक्सल कैडर की तलाश में उनके समर्थकों, शुभेच्छुओं और परिजनों को भारी परेशानी और यातना से गुजरना पड़ता है।"

लेकिन, फैसला हो चुका था और आगत सांचे में ढलती गयी है। इस बीच सभी सम्बंधित 8 राज्यों में नक्सल विरोधी एलीट बलों की स्थापना पूरी हो ली। 2009 के बाद केवल झारखण्ड (2010), कर्नाटक (2013) और छतीसगढ़ (2016) ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इन वर्षों में केवल पश्चिमी बंगाल में एक बार (2011) शांति वार्ता हो सकी है। दो सर्वाधिक प्रभावित राज्यों, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक में भी आखिरी बार 2012 में नक्सल सन्दर्भ में कोई उललेखनीय आर्थिक पहल हुई थी। तब नक्सल सन्दर्भ में यह सवाल कहीं नहीं जाने वाला कि क्या राजनीतिक समाधान ताक पर रखकर पुलिस ऑपरेशन सफल होंगे?

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

'आत्मनिर्भर भारत' वाली लक्ष्मी पीएम से पूछ रही हैं अपने पक्के मकान का ठिकाना!

जेके सिंह

लक्ष्मी देवी कोलकाता के बहू बाजार के मलांगा लेन में 80 वर्ग फुट के एक कमरे में किराए पर रहती हैं। जब कमरे का रकबा ही 80 वर्ग फुट हो तो उसमें स्नान घर और शौचालय होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लक्ष्मी देवी की बस एक ही तमन्ना है कि अगर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो जाए तो उनसे अपने पक्के मकान का ठिकाना पूछ लें।

आप हैरान हो रहे होंगे कि ये लक्ष्मी देवी कौन हैं और प्रधानमंत्री उसे उसके पक्के मकान का ठिकाना क्यों कर बताएंगे। दरअसल यह लक्ष्मी देवी वही महिला हैं, जिनकी तस्वीर मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विज्ञापन में छपी है। इस तस्वीर में पीछे एक पक्का मकान दिख रहा है। इसमें कहा गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह पक्का मकान मिला है। वे अब आत्मनिर्भर बन गई हैं। यह तस्वीर केंद्र सरकार की तरफ से जारी एक विज्ञापन में छपी थी।

भाजपा की तरफ से भी मोदी की आवास योजना की सफलता का बखान करते हुए यह तस्वीर प्रकाशित की गई थी। इसलिए उनकी तमन्ना है कि एक बार मोदी जी से मुलाकात हो जाए तो उनसे अपने इस पक्के मकान का ठिकाना पूछ लें। भव्य न सही एक साधारण सा गृह प्रवेश का आयोजन करके अपने पक्के मकान में चली जाएं जो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है। पर मोदी जी से उनकी मुलाकात मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहां तो 'तुम हो फलक पर हम हैं जमीं पर तुम्हें क्या खबर है हमारी' जैसा माजरा है।

यह सही भी है, क्योंकि मोदी जी और उनकी सरकार को लक्ष्मी देवी की हकीकत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके पति का निधन काफी पहले हो गया था। उन्होंने ठेका मजदूरी करके अपने तीन बेटे-बेटियों को पाला-पोसा और बड़ा किया। कोई शिक्षा नहीं दे पाईं, क्योंकि इतनी हैसियत नहीं थी। कमरे का रकबा कुल 80 वर्ग फुट होने के कारण बेटा फुटपाथ या अपने रिक्शा वैन पर रात को सोता है। लड़कियां घर में सोती हैं। पूरा परिवार एक

साथ कमरे में रह सके, इसकी गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद उसे आत्मनिर्भर भारत में एक पक्के मकान की मालकिन बता कर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया है।

आप हैरान हो रहे होंगे कि जब लक्ष्मी देवी की प्रधानमंत्री से मुलाकात ही नहीं हुई तो मुस्कुराते हुए मोदी के साथ तस्वीर कैसे छप गई। दरअसल यही तो भाजपा के 'गोवेल्स डिपार्टमेंट' का कमाल है। लक्ष्मी देवी बताती हैं कि गंगासागर मेले में वे ठेका मजदूर के रूप में काम करने गईं थीं। इसी दौरान कुछ फोटोग्राफरों ने उनकी तस्वीर खींची थी। उन्होंने भी तस्वीर खिंचवा ली थी। उन्हें क्या पता था यह तस्वीर आगे जाकर क्या गुल खिलाने वाली है। उनकी इन्हीं तस्वीरों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत वाला विज्ञापन तैयार किया गया। केंद्र सरकार का यह विज्ञापन 14 और 25 फरवरी को आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बांग्ला के नाम से छपा था। पर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। यह तो भाजपा के 'गोवेल्स डिपार्टमेंट' का एक नमूना है। अब इस तरह के कितने मामले होंगे, इसका कयास ही लगाया जा सकता है।

भाजपा के नेता इस बाबत खामोश हैं, लेकिन सांसद और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता सौगत राय कहते हैं कि भाजपा का सारा कारोबार ही फर्जीवाड़े के सहारे चलता है। शाहजहां के ताजमहल के बाबत एक गीतकार ने लिखा है-'एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक'।

यहां भी एक शहंशाह ने लक्ष्मी देवी का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक सरहद के विस्तार के लिए किया है। अब लोग लक्ष्मी देवी का मजाक उड़ा रहे हैं। रिक्शा वैन चलाकर रोजी-रोटी कमाने वाला उनके बेटे राहुल प्रसाद कहते हैं कि जो तस्वीर पूरे देश में दिखाई गई है, उसे सच तो साबित कर दो। अपने झूठ के मकड़जाल से बाहर निकल कर, अगर हो सके तो बस इतनी भर मेहरबानी कर देना।

(जेके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और पश्चिम बंगाल में रहते हैं।)

इस बाबा को इतनी सुरक्षा क्यों, आरएएफ मुख्यालय में जाने की अनुमति किसने दी

पुलिस के साये में हरिद्वार में घुमक्कड़ी

शिष्यों के साथ गंगा में डुबकी लगाकर कोरोना को ठेंगा दिखाता बाबा

आरएएफ मुख्यालय में बाबा

वर्दीधारी शिष्यों को प्रसाद

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: इस फोटो में जो साधू आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम इंद्रप्रस्थ एवं हरियाणा पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य है। सिद्धदाता आश्रम के नाम से इनका आश्रम फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में है। इन्होंने और इनके चेलों ने इस बाबा के हरिद्वार भ्रमण का फोटो सोशल मीडिया पर डाला है। उस फोटो में इस बाबा के साथ -साथ हरियाणा पुलिस भी चल रही है। ये पुलिस वाले फरीदाबाद के विभिन्न थाना और चौकियों में तैनात थे, जिनकी ड्यूटी अब इस बाबा की सुरक्षा में लगा दी गई है। जनता के टैक्स से चलने वाली सरकार किस धर्म खाते में इन पुलिस वालों की तैनाती ऐसे बाबाओं के लिए करती है, यह समझ से बाहर है। इन बाबाओं का सीधा संपर्क तो ऊपर वाले से रहता है, फिर भी इन्हें पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ती है।

सिद्धदाता आश्रम के ये बाबा हरिद्वार जाते हुए मेरठ में 108 आरएएफ बटालियन के मुख्यालय के अंदर गए, जहां इन्होंने आरएएफ के अफसरों, जवानों और उनकी पत्नियों को प्रसाद बांटा। काफी देर रुके और फोटो खिंचवाते रहे। उस फोटो को बाबा ने सोशल मीडिया पर भी डाला, ताकि भक्तों पर उस फोटो के जरिए धाक जमाई जा सके। आरएएफ का मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र होता है, वहां किसी प्राइवेट शख्स को जाने की अनुमति नहीं होती है। इसके बावजूद इस बाबा को जाने की अनुमति सीआरपीएफ के किस अधिकारी ने दी। बाबा के वहां जाने पर आरएएफ के आइजी आरएम मीणा, आरएपीओ के डीआईजी एके सिंह, आरएएफ 108 बटालियन के कमांडेंट राजेन्द्र प्रसाद, सीआरपीएफ 65 बटालियन के कमांडेंट वीके सिंह प्रमुख रूप से मौजूद थे। बाबा ने फेसबुक पेज पर इन अफसरों और जवानों को अपना शिष्य लिखा है।